



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 314]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय(वाणिज्य विभाग)(व्यापार उपचार महानिदेशालय)जांच शुरुआत संबंधी सूचनानई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019मामला सं. (ओ.आई.) 17/2019

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पॉलीइथिलीन ट्रेफ्थालेट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/24/2019—डीजीटीआर.—यतः, मै. आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (जिन्हें आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष टीपीएम कंसलटेंट के माध्यम से संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित 'पॉलीइथिलीन ट्रेफ्थालेट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क (अंतरिम शुल्क लगाए जाने सहित) लगाने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

1. विचाराधीन उत्पाद "वरजिन पॉलीइथिलीन ट्रेफ्थालेट (पीईटी) रेजिन" है, जिसे 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या अधिक की अंतरनिहित विस्को स्थिति वाले "पॉलीइथिलीन ट्रेफ्थालेट रेजिन" के रूप में परिभाषित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रीसाइकल्ड पीईटी रेजिन शामिल नहीं हैं। पी ई टी रेजिन का उपयोग प्री फार्म्स के

विनिर्माण में होता है जिसे बाद में मिनरल वाटर, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, खाद्य सेल, भेषज उत्पादों आदि की स्टोरेज के लिए पैट बोटल या जार में बदला जाता है।

2. पैट रेजिन को कोड 39076100 और 39076910 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, 02 फरवरी, 2017 से पहले ये वस्तुएं कोड 39076010 और 39076020 के अधीन वर्गीकृत की जाती हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

3. आवेदको ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह आवेदन मै. आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। मै. आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. आरोपित पाटित वस्तुओं के एक निर्यातक से संबंधित है। तथापि, उक्त संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की कम मात्रा पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर मै. आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. को पात्र घरेलू उद्योग माना है। प्राधिकारी ने यह माना है कि दोनों आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. शामिल देश

5. वर्तमान जांच चीन जनवादी गणराज्य ("चीन जन.गण.") के विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

ड. सामान्य मूल्य

6. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और उसमें नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के आधार पर किया गया है।

च. निर्यात कीमत

7. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय और वैट अंतर के लिए आवश्यक समायोजनों के पश्चात निर्धारित किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति का पाटित आयातों की समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री/कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण और बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आपय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में परिणामी विकृति के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
10. संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं जो जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

11. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. जांच अवधि (पीओआई)

12. आवेदक ने जांच अवधि के लिए सितंबर, 2018 से मार्च, 2019 (6 माह) तक का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने 1 सितंबर, 2018 से 30 जून, 2019 (9 माह) की अवधि को जांच अवधि के रूप में उचित माना है। क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत करा सकें।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार को अन्य पक्षों को इसे उपलब्ध कराने के लिए इसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

ड. समय-सीमा

15. वर्तमान से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना

प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) को सूचित करें तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ढ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
18. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
22. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

त. असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

थ. प्रतिदर्श

25. इस कार्यवाही में संबद्ध देश से बड़ी संख्या में शामिल निर्यातक (कों)/उत्पादक (कों) द्वारा भागीदारी की संभावना और जांच पूरी करने की सीमित समयवधि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच किए जाने वाले निर्यातक (निर्यातकों)/उत्पादक(उत्पादकों) को प्रतिदर्श का चयन करके तर्कसंगत संख्या तक सीमित कर सकते हैं। नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार, यदि अपेक्षित होगा, तो प्रतिदर्श लिया जाएगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi the 1st October, 2019

Case No. (O.I.) 17/2019

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Polyethylene Terephthalate" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/24/2019-DGTR.—Whereas M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) have jointly filed an application through TPM Consultants before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty (including imposition of interim duty) on imports of "Polyethylene Terephthalate" originating in or exported from China PR (also referred to as the “subject country”).

A. Product under consideration

1. The product under consideration is “virgin polyethylene terephthalate (PET) resin”, defined as “polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”. The scope of product under consideration does not include recycled PET resin. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottle and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc.
2. PET resin is classified under the codes 39076100 and 39076910. However, prior to 2nd February, 2017, the goods were classifiable under the codes 39076010 and 39076020. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of present investigation.

B. Like article

3. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. The Authority has treated the subject goods produced by the domestic industry as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic industry and standing

4. The application has been jointly filed by M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited. M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited is related to an exporter of the alleged dumped goods. However, considering the small volume of exports by the said related entity, the Authority has considered M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The Authority has considered that both the applicant producers constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and the application satisfies the standing requirement under Rule 5(3) of the Rules supra.

D. Country involved

5. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from People's Republic of China ("China PR").

E. Normal value

6. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. Normal value has been determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expense and reasonable profits.

F. Export price

7. The applicants have claimed export price on the basis of DGCI&S transaction wise import data. The net ex-factory export prices have been determined after due adjustments towards of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, inland freight expenses and VAT difference.

G. Dumping margin

8. The normal value has been compared with export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the export price, showing that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin estimated is above de minimis.

H. Evidence of injury and causal link

9. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price suppression/depression, price underselling, and consequent deterioration in performance of the domestic industry in respect of market share, profitability, cash profits and return on capital employed.
10. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country to justify initiation of investigation.

I. Initiation of Anti-Dumping Investigation

11. The Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to justify initiation of an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the

injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of Investigation (POI)

12. The applicants have proposed the period September, 2018 to March, 2019 (6 months) as the investigation period. However, the Authority considers it appropriate to consider the period of investigation as the period 1st September, 2018 to 30th June, 2019 (9 months). The injury investigation period shall cover 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.

K. Submission of information

13. Known exporters in the subject country, Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time limit

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within 40 days from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

M. Submission of information on non-confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response / submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page
18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible
20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of public file

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. Sampling

25. In view of the potentially large number of exporting producers from the subject country involved in this proceeding and in order to complete the investigation within the stipulated time limits, the Authority may limit the exporter(s)/ producer(s) to be investigated to a reasonable number by selecting a sample. The sampling shall be carried out, if required, in terms of Rule 17(3) of the Rules.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General